

नवा भारत



65वां वर्ष

संस्करण



5 आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस अपनाए दुनिया



6 घरेलू पिचों पर हम बार-बार क्यों हारते हैं



7 वित्त मंत्री ने स्टार्टअप के साथ की बैठक



8 डब्ल्यूपीएल 2026 की नीलामी दिल्ली में 27 को



एक नजर में

अल-फलाह के 25 ठिकानों पर छापे

ईडी ने हरियाणा के फरीदाबाद सहित कई शहरों में की कार्रवाई

नई दिल्ली, 18 नवंबर (वार्ता). दिल्ली विस्फोट मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय और दिल्ली के ओखला स्थित कार्यालय समेत 25 से अधिक परिसरों पर छापे मारे हैं. यह छापेमारी दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट से जुड़े धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की विस्तारित जांच का एक हिस्सा है.

ईडी टीमों ने मंगलवार सुबह 5:15 बजे शुरू यह कार्रवाई की. जांचकर्ताओं ने संस्थान के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त होने के दावों में पहली नजर में विसंगतियां पाई हैं. इन पहलुओं की अब संबंधित नियामक प्राधिकरणों से पुष्टि की जा रही है. पुलिस प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई ईडी की जांच



अब आतंकवाद से जुड़ी जांच से बढ़कर एक जटिल वित्तीय धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में बदल गई है, जिससे संस्थान के वित्तीय अपराधों और विस्फोट के आरोपियों की गतिविधियों के बीच गहरी सांठगांठ का संकेत मिलता है. इसके अलावा लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच पश्चिम बंगाल तक जा पहुंची है. सूत्रों ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में

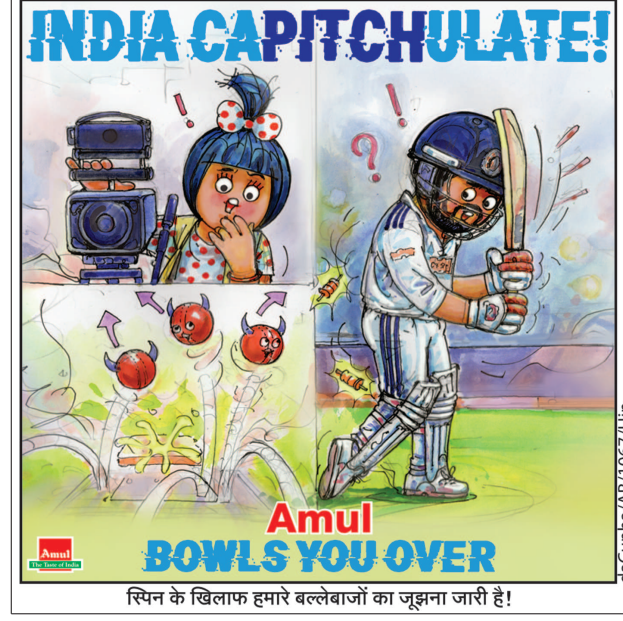
बंद एक आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी साबिर अहमद पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पलाशीपारा इलाके का रहने वाला है. फिलहाल, वह ड्रग्स से जुड़े एक मामले में प्रेसीडेंसी जेल में बंद है. लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए जोरदार धमाके में मौत का आंकड़ा अब 15 पहुंच गया है. एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के दौरान दो और घायलों की मौत हो गई. अस्पताल और पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है.

एनआईए की मांग पर आरोपी जसीर को 10 दिन की रिमांड आतंकी हमले के मामले में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की मांग पर कोर्ट ने आरोपी जसीर को 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है. जासिर बिलाल आतंकी उमर का सहयोगी है. उसकी रिमांड मिलने से जांच एजेंसी को धमाके के पीछे की साजिश का पता चल सकेगा. जसीर की गिरफ्तारी से ब्लास्ट के तार कश्मीर से जुड़ गए हैं.

खतरनाक इरादों के साथ बुनी गई आतंकी साजिश



दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियों को उमर का वीडियो हाथ लगा है. इस वीडियो में वह सुराइट बॉयिंग की पैरवी करता दिखाई दे रहा है. ऐसे में जांच एजेंसियों को यकीन हो गया है कि दिल्ली बम धमाके को आतंकी डॉक्टरों ने किसी हड़बड़ी में अंजाम नहीं दिया था. ये बेहद सोची समझी और खतरनाक इरादों के साथ बुनी गई आतंकी साजिश थी. वही दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां हरियाणा के फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसती जा रही हैं. जांच एजेंसियों ने आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉ. निसार उल हसन की डॉक्टर पत्नी और एमबीबीएस कर रही बेटी को यूनिवर्सिटी कैम्पस में ही गिरफ्तार किया है. इसके अलावा एमबीबीएस के 10 और छात्रों के यूनिवर्सिटी कैम्पस से बाहर जाने पर रोक लगाई गई है. इनके मोबाइल जांच एजेंसियों के पास हैं. मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग व अन्य डेटा चेक किया जा रहा है.



स्पिन के खिलाफ हमारे बल्लेबाजों का जूझना जारी है!

इस्पात संयंत्र कर रहा प्रगति: कुमारस्वामी

राउरकेला, 18 नवंबर. केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने मंगलवार को 2025 को सेल, राउरकेला इस्पात का दौरा किया।

कुमारस्वामी राउरकेला संयंत्र (आरएसपी) के दो दिवसीय दौरे पर यहां आये हैं और उनके साथ सेल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अमरेंद्र प्रकाश और इस्पात मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी थे। इस अवसर पर कुमारस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत सरकार राउरकेला इस्पात संयंत्र को वृद्धि और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओराम ने आरएसपी कर्मियों से प्रयासों की सराहना की और संयंत्र से जुड़ी अपनी स्मृतियों को याद करते हुए इस्पात संयंत्र की प्रगति के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

छग में खूंखार नक्सली हिडमा का खात्मा

24 से अधिक हमलों का मास्टरमाइंड था हिडमा

01 करोड़ रुपए का इनाम था हिडमा पर

रायपुर/सुकमा, 18 नवंबर (वार्ता) देश में कुख्यात माओवादी कमांडर मादवी हिडमा सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मंगलवार को मारा गया, उसके साथ ही उसकी पत्नी महुकम राजे भी मारी गई. हिडमा 24 से अधिक बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका था, उसे 2013 के दरभा



घाटी नरसंहार और 2017 के सुकमा हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया था. बता दें कि बस्तर क्षेत्र से सेंट्रल कमेटी में शामिल एकमात्र आदिवासी सदस्य हिडमा के सिर पर केंद्र और विभिन्न राज्यों की ओर से कुल लगभग एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था, जिसमें अकेले केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपये का इनाम रखा था.

डीजीपी ने जगदलपुर में यूनिवर्सिटी से बात करते हुए बताया कि मुठभेड़ में हिडमा समेत छह नक्सली मारे गए हैं, जिनकी पहचान हिडमा - सेंट्रल कमेटी सदस्य (सीसीएम), महुकम राजे (पत्नी) - (एसजेडसीएम), लकमल - डीसीएम, कमलु - पीपीसीएम, मल्ला - पीपीसीएम और देवे - हिडमा का गाई के रूप में हुयी है. सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से दो एके-47, एक रिमॉन्ड और एक पिस्टल बरामद की है.

छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गोतम ने आज हिडमा के मारे जाने की पुष्टि की.

सुको के निशाने पर जांच एजेंसियां

खातों में हेराफेरी व संस्थागत मिलीभगत का है आरोप

नई दिल्ली, 18 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और व्यवसायी अनिल अंबानी से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है.

इस याचिका में रिलायंस कन्सल्टिंग (आरकॉम) और इस समूह की अन्य संस्थाओं की ओर से कथित तौर पर बैंकों के ऋण के दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर हुई बैंक धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच की



मांग की गई है. केन्द्र सरकार के पूर्व सचिव ईएएस सरमा की ओर से दायर इस याचिका में भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में से एक में धन के व्यवस्थित दुरुपयोग, खातों में हेराफेरी और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने नोटिस जारी कर केंद्र, सीबीआई, ईडी और अंबानी को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार

43 नेताओं को थमाया कारण बताओ नोटिस

21 नवंबर तक मांगा गया लिखित स्पष्टीकरण

पटना, 18 नवंबर. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ गई है. पार्टी को प्रदेश इकाई ने संगठन-विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने ही 43 नेताओं को कारण पत्र जारी किया है. इन

आलोचना करने वाले नेताओं को भेजा नोटिस

अब जब पार्टी ने आलोचना करने वाले नेताओं को नोटिस भेजा है, तो असंतोष और गहरा हो गया है. नाराज नेताओं का आरोप है कि संसाधनों की कमी और कमजोर नेतृत्व पर सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहा है.

सभी से 21 नवंबर दोपहर 12 बजे तक लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है. कांग्रेस के आदेश के अनुसार, चुनाव अवधि के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया और अन्य मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए, जिससे संगठन की छवि और चुनावी प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ा. प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने पुष्टि की कि नोटिस उन नेताओं को भेजे गए हैं, जिनकी गतिविधियां पार्टी अनुशासन के विरुद्ध पाई गईं. चुनाव अभियान के समय ही कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी उभर आई थी. स्थानीय नेताओं की अनदेखी, बंद कमरे में रणनीति तैयार करने और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों को लेकर कई नेताओं ने खुलकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए थे. कई ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और चुनाव प्रभारी कृष्णा अल्लावार को शैली को हार की मुख्य वजह बताया था.

ईरान ने भारतीयों के लिए बंद कर दी फ्री वीजा एंट्री

नया नियम 22 नवंबर से होगा लागू

भारत के विदेश मंत्रालय ने की एडवाइजरी जारी

तेहरान, 18 नवंबर. ईरान ने भारतीयों के लिए 22 नवंबर से बिना वीजा प्रवेश की सुविधा बंद कर दी है. यह कदम उस समय उठाया गया, जब कई भारतीयों को नकली नौकरी हिलाने के नाम पर ईरान भेजने, वहां तस्करी करने और फिरौती के लिए अगवा करने जैसी घटनाएं लगातार सामने आईं. सरकार ने साफ कर दिया है कि यह प्रतिबंध सभी भारतीय

शशि थरुर ने की पीएम मोदी के भाषण की तारीफ

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कांग्रेस नेता शशि थरुर के सुर बदले नजर आ रहे हैं. कांग्रेस सांसद होने के बावजूद शशि थरुर अवसर सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी समेत सरकार के कई फैसलों की सराहना करते दिखाई देते हैं. दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान को संबोधित करते हुए 2035 तक भारत की मैकाले की मानसिकता से निकालने की हुंकार भरी थी. पीएम मोदी के भाषण के दौरान ऑडियंस की कतार में शशि थरुर भी मौजूद थे.

योजनाएं चढ़ीं परवान

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोलर पंप स्थापना की योजना में संशोधन को दी मंजूरी

3 एचपी वाले 5 और 5 वाले 7.5 एचपी का लगा सकेंगे सोलर पंप

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 18 नवंबर. प्रदेश में अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को सोलर पंप लगाने के लिये बड़ी रियायत दी जाएगी. ऐसे किसान जिनके पास 3 एचपी का अस्थायी कनेक्शन है, वे 5 एचपी तक का सोलर पंप लगा सकेंगे, वहीं 5 एचपी अस्थायी कनेक्शन वाले किसान 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले सोलर पंप लगा सकेंगे. कैबिनेट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य

योजना में सिंचाई के लिये सोलर पंप स्थापना की योजना में संशोधन की मंजूरी दे दी है. निर्णय के तहत योजना के पहले चरण में अस्थायी विद्युत कनेक्शन संयोजन वाले किसानों अथवा अविद्युतीकृत किसानों को सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा. योजना अनुसार 7.5 एचपी क्षमता तक का सोलर पंप पंप लगाने के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन धारी कृषक का अंश 10 फीसदी रहेगा. वहीं राज्य सरकार 90 फीसदी सब्सिडी देगी.



कैबिनेट ने प्रदेश के 12 जिलों भोपाल, इन्दौर, नरसिंहपुर, मण्डलेश्वर (खरगौन), बालाघाट, गुना,

भिण्ड, सोहोर, अमरकंटक (अनूपपुर), पन्ना, श्योपुर एवं शुजालपुर (शाजपुर) में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों एवं बड़वानी जिले में 30 बिस्तरीय चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 पट्ट एवं 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल की मंजूरी दी है. स्वीकृत नवीन पदों में प्रथम श्रेणी के 52 पद, द्वितीय श्रेणी के 91 और तृतीय श्रेणी के 230 पद शामिल हैं. नियमित पदों पर वार्षिक वित्तीय भार 25 करोड़ 57 लाख रुपये आयेगा. इसके साथ ही

स्वीकृत मानव संसाधन सेवाओं में द्वितीय श्रेणी के 91, तृतीय श्रेणी के 117 और चतुर्थ श्रेणी के 598 पद शामिल हैं. प्रदेश में अब ऐसे बच्चे जो कि बेघर हैं या फिर प्राकृतिक आपदा से पीड़ित, बाल श्रमिक, बाल वेश्यावृत्ति के शिकार हैं या फिर एड्स पीड़ित, बाल शिशुक, सड़क पर रहने वाले, घर से भागे, लापता, शोषण और दुर्व्यवहार के शिकार श्रेणी के हैं, ऐसे बच्चों को अब सरकार प्रतिमाह 4 हजार रुपये तक देगी. कैबिनेट ने मिशन वात्सल्य

यह निर्णय भी लिए

- मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में भर्ती के लिए सेवा शर्तें एवं नियम अनुमोदित
- मेडिको लौगल संस्थान के अधिकारियों को पुनरीक्षित (सातवें) वेतनमान का वास्तविक लाभ प्रदान किया जाएगा.
- प्रदेश में क्रियान्वित सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना में संशोधन. आयुक्त, संस्थागत वित्त को राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का सदस्य सचिव के रूप में नामित. योजनान्तर्गत 100 करोड़ का बजट प्रावधान.
- नव गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर-मालवा के लिए 9 नवीन पदों का सृजन.

योजना के तहत गैर संस्थागत सेवा योजना यथा स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, आप्टर केयर को आगामी 5 वर्षों तक प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित करने की मंजूरी दी है.